राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 07 जनवरी 2026

वर्ष 14,अंक 264, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

सामुदायिक शौचालयों में करोड़ों का खेल!..03

दोना, पत्तल की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान..04

निकोलस मादुरो को उठाकर ले गया अमेरिका तब क्या कर रही थी वेनेजुएला सेना? एक्सपर्ट ने बताई ट्रंप की सीक्रेट डील

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी डेल्टा फोर्स के जवानों ने शनिवार तड़के एक बेहद सटीक और तेज सैन्य अभियान को अंजाम दिया. हेलीकॉप्टरों के जरिये कमांडो दस्ते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ठिकाने तक पहुंचे, परिसर पर धावा बोला और उन्हें लगभग बिना किसी बड़े टकराव के अपने साथ ले गए. इस ऑपरेशन में बेहद सीमित नुकसान हुआ. केवल एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मामूली नुकसान पहुंचने और कुछ जवानों के घायल होने की खबर है. हालांकि, इस मिशन की सफलता के पीछे सिर्फ अमेरिकी सैन्य ताकत ही कारण नहीं मानी जा रही है. स्वतंत्र सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि वेनेजुएला की सेना की ओर से लगभग न के बराबर प्रतिरोध यह संकेत देता है कि मादुरो शासन के भीतर के कुछ तत्वों और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ था, जिसने इस कार्रवाई को आसान बना दिया।

सेना की चुप्पी ने खड़े किए सवाल

तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में यूएस स्टडीज प्रोग्राम के प्रमुख ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) अनिल रमन के मुताबिक, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों या यहां तक कि साधारण हथियारों से भी निशाना बनाया जा सकता था. इसके बावजूद किसी बड़े जवाबी हमले के संकेत नहीं मिले. रमन कहते हैं, 'उपलब्ध सबूत यही दिखाते हैं कि वेनेजुएला की सेना ने अमेरिकी बलों से टकराव से परहेज किया. भले ही वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय कर दी गई हों, लेकिन उसके पास हजारों इग्ला मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं, जिनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं हुआ. यह किसी सौदे की ओर इशारा करता।

'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व'

अमेरिकी सेना के इस मिशन को 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' नाम दिया गया था. ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन के अनुसार, इस अभियान में 150 से अधिक विमान शामिल थे, जिनमें लड़ाकू विमान, बॉम्बर और ड्रोन शामिल थे. इनकी मदद से वेनेजुएला की रूसी मूल की एयर डिफेंस सिस्टम्स को निष्क्रिय किया गया. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ वायु रक्षा प्रणाली बर्बाद करने से यह स्पष्ट नहीं होता कि जमीनी बलों ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को चुनौती क्यों नहीं दी. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक मौके पर भारी गोलीबारी हुई, जिसमें 12 अमेरिकी जवान घायल हुए, लेकिन यह प्रतिक्रिया उस स्तर की नहीं थी जिसकी आशंका पहले जताई जा रही थी।

डेल्सी रोड्रिगेज के रोल पर भी चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को मादुरो के उत्तराधिकारी के रूप में अमेरिकी प्रशासन की तरफ से मौन स्वीकृति दे दी प्रतीत होती है. उन्होंने अंतरिम नेता के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेल्सी और उनके भाई जॉर्ज रोड्रिगेज, जो नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं, ने बीते साल अमेरिकी प्रशासन से गुप्त बातचीत की थी, जिसमें अरब देशों के मध्यस्थ भी शामिल थे. मायामी हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, इन वार्ताओं में दो प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, जिनमें मादुरो के सत्ता छोड़ने और एक अंतरिम सरकार के गठन की बात थी. एक प्रस्ताव में मादुरो को देश में ही सुरक्षा देने की बात थी, जबकि दूसरे में उन्हें तुर्की या क़तर में निर्वासन का विकल्प दिया गया था. हालांकि, किसी भी प्रस्ताव में उनकी गिरफ्तारी शामिल नहीं थी।

आगे क्या होगा वेनेजुएला का भविष्य?

विश्लेषकों का मानना है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला का भविष्य कई दिशाओं में जा सकता है. ब्रिगेडियर रमन के अनुसार, एक संभावना यह है कि डेल्सी रोड्रिगेज सेना के समर्थन से सत्ता संभालें और देश में स्थिरता बनी रहे. दूसरी संभावना यह है कि विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को देश की कमान मिले, जिससे तनाव बढ़ सकता है. तीसरी और सबसे गंभीर आशंका देश में गुटीय या गुरिल्ला हिंसा के फैलने की है. फिलहाल, मादुरो की गिरफ्तारी ने न केवल वेनेजुएला बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल तेज कर दी है और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

मौत की घाटी में बदल गई मेरी जन्मभूमि, फेसबुक पर लिखा था पोस्ट, 17 दिन बाद हो गई हिंदू मणि की हत्या

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर हाल के दिनों में लगातार हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे देश में सुरक्षा और सामाजिक तनाव की स्थिति गंभीर होती जा रही है. केवल पिछले 24 घंटों में दो ऐसे जानलेवा हमले हुए हैं, जिनमें हिंदू समुदाय के दो निर्दोष लोगों की मौत हो गई. पिछले दो महीने में हिंदुओं की हत्याओं ने बांग्लादेश में दूसरे धर्मों को लेकर कैसा माहौल है, ये उजागर कर दिया है. मणि चक्रवर्ती और एक अन्य व्यक्ति की हत्या ने इस स्थिति को और ज्यादा चिंताजनक बना दिया है।

मणि चक्रवर्ती नरसिंदी जिले के चारसिंदुर बाजार में अपनी किराने की दुकान चलाते थे, जिनकी सोमवार की रात अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मणि को गंभीर चोटें आई, और उन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में या अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई. मणि ने अपने फेसबुक पोस्ट में 17 दिन पहले ही देश में बढ़ती हिंसा और अशांति के बारे में अपनी चिंता जताई थी. उनकी पोस्ट ने बांग्लादेश में हिंदुओं के डर और अनहोनी की आशंका को जाहिर कर दिया है।

'मेरी जन्मभूमि मौत की घाटी बन गई है'

बांग्लादेश में हत्या होने से पहले मणि चक्रवर्ती ने अपने फेसबुक पोस्ट में देश की वर्तमान स्थिति को लेकर दर्द और चिंता व्यक्त की थी. उन्होंने लिखा था- 'यहां हर जगह आग है, इतनी हिंसा फैल गई है. मेरा जन्मस्थान आज मौत की घाटी जैसा हो गया है.' ये पोस्ट उन्होंने 19 दिसंबर को किया था, जिसमें उन्होंने देश में बढ़ती हिंसा और अशांति के कारण गहरी निराशा जताई थी. कुछ रिपोर्टों के अनुसार मणि शांत और मिलनसार व्यक्ति थे और उनकी यह पोस्ट दिखाती है, उस भय और परेशानी का जो उन्होंने अपने समाज में महसूस की थी. यह पोस्ट उनके हत्याकांड से पहले किया गया अहम सोशल मीडिया संदेश माना जा रहा है, जो बांग्लादेश में जन्मे हिंदुओं के डर को बयां किया है।

अल्पसंख्यकों के लिए नर्क बना बांग्लादेश

इन हमलों ने हिंदू समुदाय में गहरा डर पैदा कर दिया है. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कहना है कि उनका जीवन अब असुरक्षित महसूस हो रहा है. बाजार, मंदिर और घर, कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश की सामाजिक संरचना और धार्मिक सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की हिंसा का मुख्य कारण धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता है. राजनीतिक और धार्मिक समूहों के बीच तनाव बढ़ने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करना आसान हो जाता है।

मणिपुरः बिष्णुपुर में आईईडी विस्फोटों में दो नागरिक घायल, एनआईए करेगा जांच

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली– मणिपुर के मेईतेई-बहुल बिष्णुपुर जिले में सोमवार (5 जनवरी) सुबह लगातार हुए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोटों में कम से कम दो नागरिक घायल हो गए. इस घटना ने हिंसा-ग्रस्त राज्य में पहले से नाजुक सुरक्षा स्थिति को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दीं. इस बीच, अधिकारियों ने मंगलवार (6 जनवरी) को बताया कि इन दोहरे धमाकों की जांच एनआईए को सौंप दी गई है. ये धमाके कुकी-ज़ो-बहुल चूड़चांदपुर जिले की सीमा से लगे फौगाकचाओ पुलिस स्टेशन के तहत सैतों-नगानुखोंग इलाके में एक सुनसान घर में सुबह 5:40 बजे से 5:45 बजे के बीच हुए. तीसरा धमाका सुबह करीब 8:45 बजे हुआ, जो पहले धमाके वाली जगह से लगभग 200 मीटर दूर था. घायलों की पहचान सनातोंबा सिंह और इंदुबाला देवी के रूप में हुई है. पहले धमाके के बाद घटनास्थल का मुआयना करते समय उनके दाहिने पैरों में छर्रे लगे. दोनों का एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. जिस घर में धमाके हुए, वह एक ऐसे निवासी का है जो 3 मई 2023 को मेईतेई-कुकी समुदायों के बीच हिंसा शुरू होने के बाद से राहत शिविर में रह रहे हैं. इस जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं. इस बीच, राज्य पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, मामले को आगे की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भेज दिया गया है. इसमें कहा गया है, 'आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, और हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है. धमाकों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए जांच और ऑपरेशनल प्रयास जारी हैं।'

मेईतेई और कुकी-ज़ो संगठनों ने घटना की निंदा की

सोमवार के विस्फोट ऐसे समय में हुए हैं जब प्रशासन आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को उनके मूल गांवों में पुनर्वासित करने का प्रयास कर रहा है. मेईतेई और कुकी-ज़ो - दोनों संगठनों ने इस हिंसा की निंदा करते हुए इसे शांति प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बताया है. इंडिजिनस पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन और ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन सहित कई संगठनों ने धमाके के विरोध में बुधवार (7 जनवरी) को सुबह 12 बजे से पूरे राज्य में 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है. मेईतेई नागरिक संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (कोकोमी) ने धमाकों की तत्काल, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है. हिंसा की इस ताज़ा कड़ी से क्षेत्र में तनाव फैल गया. नाराज़ स्थानीय लोगों ने पास के एक सीआरपीएफ बंकर को तोड़ दिया और अर्धसैनिक बल पर हमले को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया. अधिकारियों ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है. 16 दिसंबर को इसी सीमा क्षेत्र में चूड़ाचांदपुर की ओर से अज्ञात बंदूकधारियों ने बिष्णुपुर के मेईतेई बस्तियों पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे।

मेईतेई हेरिटेज सोसाइटी (एमएचएस) ने एक बयान में हमले के लिए 'संदिग्ध चिन-कुकी उग्रवादी/सशस्त्र समूहों' को ज़िम्मेदार ठहराया. एमएचएस ने कहा, 'और भी अधिक चिंताजनक यह है कि यह हमला उस समय किया गया जब पास में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात थे. इससे मौजूदा सुरक्षा स्थिति और सशस्त्र समूहों द्वारा बेखौफ होकर काम करने पर गंभीर सवाल उठते हैं.' 16 दिसंबर को हुई गोलीबारी का उल्लेख करते हुए एमएचएस ने कहा, 'ताज़ा हमला भय पैदा करने, पुनर्वास को पटरी से उतारने और नाजुक सामान्य स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई सुनियोजित कोशिशों की श्रृंखला का हिस्सा है. नागरिकों को निशाना बनाना न केवल अमानवीय है, बल्कि राज्य के अधिकार और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी कमजोर करता है।'

एमएचएस ने राज्यपाल से दोषियों के खिलाफ 'त्वरित, निर्णायक और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई' सुनिश्चित करने का आग्रह किया. वहीं, कुकी-ज़ो काउंसिल (केजेडसी) ने भी विस्फोटों की निंदा की. केजेडसी के अनुसार, ये विस्फोट गामनोमफाल गांव के पास सुबह 5:40 से 8 बजे के बीच हुए, जिनमें कथित तौर पर 'कई लोग' घायल हुए. हिंसा को 'बेहद परेशान करने वाली और शांति व सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा' बताते हुए केजेडसी ने कहा कि यह घटना एक तय बफर ज़ोन में या उसके आसपास हुई - यह एक सीमांकित क्षेत्र है जिसे सुरक्षा बल समुदायों के बीच झड़पों को रोकने के लिए बनाए रखते हैं. केजेडसी ने कहा, 'बफर ज़ोन की शुचिता हर समय बनाए रखी जानी चाहिए.' और जोड़ा कि यह घटना क्रिसमस-नववर्ष के मौसम के दौरान हुई, जो शांति और सुलह का समय होता है, इसलिए ऐसी घटना होना मुख्य रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है।

केजेडसी ने मामले की गहन और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की. बता दें कि फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जब मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कुकी और मेईतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा से निपटने के लिए अपने प्रशासन की आलोचनाओं के बीच इस्तीफा दे दिया था. ये विस्फोट उस उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के दो दिन बाद हुए, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की थी. बैठक में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, राज्य के डीजीपी राजीव सिंह और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह शामिल थे।

संक्षिप्त ख़बरें

VB-G RAM G पर सीएम योगी बोले- पहले डकैती डालकर बेरोजगारी की ओर धकेला, अब बनेगी विकसित भारत की आधारशिला

लखनऊ– उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसद में विकसित भारत को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया नया अधिनियम (जी राम जी योजना) देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से अभिनंदन करते हैं।

आज उन्हें अपनी पोल खुलने का डर सता रहा...

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक संसाधनों पर डकैती डालकर देश को बेरोजगारी की ओर धकेला, आज उन्हें अपनी पोल खुलने का डर सता रहा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन विकास से जुड़े सकारात्मक कदमों का समर्थन करने के बजाय भ्रष्टाचार के अपने पुराने कारनामों को छिपाने के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी ने कहा कि जी राम जी योजना विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई तकनीक को जोड़ा जा रहा है, जिससे जल संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास संभव हो सकेगा।

जिन योजनाओं का ढोल पीटा जा रहा है, उनका...

मुख्यमंत्री ने मनरेगा पर कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन योजनाओं का ढोल पीटा जा रहा है, उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं रहा। हर जनपद से भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं। किसानों को जरूरत के समय मजदूर नहीं मिलते थे और मजदूरों को काम के समय काम नहीं मिलता था। उन्होंने बताया कि नए संशोधन के तहत योजना में कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़कर 125 कर दी गई है। समय पर काम नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते की गारंटी भी होगी। किसानों की जरूरत को देखते हुए आवश्यक समय पर मनरेगा के कार्य स्थगित रखे जाएंगे।

जो लोग केवल खोदने और भरने से लाभ उठाते थे, वो...

योगी ने कहा कि जो लोग केवल खोदने और भरने से लाभ उठाते थे, वही इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अब कार्यों को तकनीक से जोड़ा जाएगा, डिजिटल भुगतान होगा और रियल टाइम ऐप के माध्यम से निगरानी की जाएगी। योजना के अंतर्गत ऑडिट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मनरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए, जिनकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 की रहेगी, जिससे उत्तर प्रदेश को करीब 17 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिल सकेगी।

केजरीवाल का एक और दांव पड़ा उल्टा, दिल्ली विधानसभा में फांसी घर होने का दावा समिति की जांच में खारिज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने विधानसभा में ऐतिहासिक फांसी घर होने का दावा किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने उस जगह को सभी सजाया संवारा था और खूब प्रचारित किया था. लेकिन अब दिल्ली विधानसभा की समिति ने ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल के बाद साफ कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा परिसर में 'फांसी घर' होने का दावा ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित नहीं होता. जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि विधानसभा परिसर में कभी फांसी घर मौजूद।

दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने 'फांसी घर' विवाद पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह बातें कही गई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 'फांसी घर' के रूप में प्रचारित किया गया स्थान वास्तविक रूप से किसी अन्य उपयोग जैसे सेवा या टिफिन कक्ष के लिए था. समिति ने माना कि बिना ऐतिहासिक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किए, इसे फांसी घर बता दिया गया. जब दावे करने वाले नेताओं को बुलाया गया तो वे सामने नहीं आए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए. समिति ने इसे गंभीर माना है. बिना किसी कारण के समिति के समन को न मानना भी बेहद गंभीर है. कोर्ट की आड़ लेकर समिति के सामने पेश न होना बेहद गंभीर मामला है. यह आचरण विधानसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है।

कमेटी ने बुलाया, लेकिन नहीं आए केजरीवाल

समिति ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राम निवास गोयल और राखी बिड़ला को समिति की बैठकों में उपस्थित न होने का दोषी माना. रिपोर्ट में कहा गया कि 13 और 20 नवंबर को इन?हें मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन इनमें से कोई भी शामिल नहीं हुआ. समिति ने इसे विधानसभा और समिति की अवमानना करार दिया. 'फांसी घर' को लेकर किए गए ऐतिहासिक दावों को तथ्यहीन बताया गया. समिति ने कहा कि बिना प्रमाण के इतिहास को प्रस्तुत करना सदन की गरिमा के खिलाफ है. मामले में आगे की कार्रवाई और रिपोर्ट अगले सत्र में प्रस्तुत किए जाने की सिफारिश की गई है. विशेषाधिकार समिति ने दोषी पाए गए सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की है।

कैसे मिला था कमरा

दरअसल, केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा की इमारत में एक पुराना और रहस्यमयी कमरा मिला है, जो दशकों से बंद था. इसकी बनावट को देखकर इसे ब्रिटिश कालीन 'फांसी घर' माना जा रहा है. ऐसा माना जाता है कि आजादी से पहले जब अंग्रेज इस इमारत का इस्तेमाल करते थे, तो यहां भारतीय क्रांतिकारियों पर मुकदमे चलते थे और उन्हें यहीं फांसी दी जाती थी. विधानसभा अध्यक्ष ने इस जगह को संरक्षित कर इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया था, ताकि लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को जान सकें. लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो इसकी जांच कराई गई, जिसमें मामला फर्जी निकला।

वन भूमि के अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकारा, पूछा- 23 साल बाद जागे!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली– उत्तराखंड में हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्ज़े के मामले में सोमवार (5 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि 2000 में राज्य के गठन के बाद से अतिक्रमण करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने कहा कि राज्य में कार्यकारी पद पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति इस लापरवाही के लिए जवाबदेह है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राज्य को दो सप्ताह के अंदर एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है जिसमें साइट प्लान और राज्य में वन भूमि पर हुए अवैध निर्माणों की अनुमानित जानकारी दी जाए ताकि यह तय किया जा सके कि क्या आगे और गहन जांच जरूरी है. मालूम हो कि इससे पहले अतिक्रमित भूमि के स्वामित्व को लेकर कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर को वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण पर सरकार की 'चुप्पी' को लेकर सवाल उठाया था. कोर्ट ने तब सुनवाई के दौरान कहा था, 'हमें यह बात बेहद चौंकाने वाली लगती है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं, जबकि वन भूमि को उनकी आंखों के सामने सुनियोजित तरीके से हड़पा जा रहा है।'

इस मामले में अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सभी तथ्यों की जांच करने और अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था. सोमवार को सरकारी वकील ने पीठ को सूचित किया कि अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'आपका जवाब राज्य सरकार के रूप में आपकी लाचारी दर्शाता है.' वकील ने कहा कि 1993 में कार्रवाई की गई थी और 2023 में बेदखली के नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उन पर रोक लगा दी थी।

इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'तो आप कभी-कभार कार्रवाई करते रहे हैं. वह भी सिर्फ औपचारिक. कृपया राज्य के रूप में आपने क्या किया है, इस संबंध में एक उचित हलफनामा दाखिल करें.' राज्य के वकील ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि 1950 के दस्तावेज़ों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को कुछ दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी लिखा है।

अधिकारियों की लापरवाही और भूमि हड़पने वालों से मिलीभगत

मालूम हो कि साल 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग से अलग करके बनाया गया था. पीठ ने कहा, 'पहले आप अपने आचरण का स्पष्टीकरण दीजिए. आपका गठन 2000 में हुआ था. उसके बाद आपने क्या किया? नहीं तो, हम आप में से हर एक से जवाबदेही पूछेंगे. आप लोगों को उनके घर बनाने देते हैं, आप उनकी पीढ़ियों को वहां रहने देते हैं और फिर अचानक सिर्फ कोर्ट के आदेश की वजह से आप उसकी आड़ में छिपना चाहते हैं... जब कोर्ट सवाल कर रहा है.' इस पर वकील ने कहा कि राज्य ने कथित कब्जा करने वालों को बेदखली के नोटिस जारी किए हैं. चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, 'तो वर्ष 2000 से आपको यह पता लगाने में 23 साल लग गए कि आपकी जमीन पर कब्जा हो गया है.' पीठ ने आगे कहा, 'हम आपके हर अधिकारी को जवाबदेह ठहराएंगे. ऊपरवाला जाने अतिक्रमणकारी कौन हैं, किस राजनेता या किस अधिकारी के साथ मिले हुए हैं या कौन से प्रभावशाली व्यक्ति उनके साथ सांठगांठ कर रहे हैं।'

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, 'हमने जांच समिति द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट का अध्ययन किया है. ... रिपोर्ट दशकों से सरकारी/वन भूमि की रक्षा करने में राज्य तंत्र की चौंकाने वाली विफलता को दर्शाती है. ऐसा प्रतीत होता है कि जिस भूमि पर वर्षों से सुनियोजित रूप से अतिक्रमण किया जा रहा था, उस पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की औपचारिकता 2023 में कुछ नोटिस जारी करके पूरी की गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी और अधिकारी फिर से निष्क्रिय हो गए.' अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में राज्य के अधिकारी लगातार और निरंतर लापरवाह रहे हैं और यह भूमि हड़पने वालों के साथ मिलीभगत और सांठगांठ का मामला प्रतीत होता है. पीठ ने कहा, 'हम कुल भूमि का विवरण और उस पर कथित तौर पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों की संख्या जानना चाहेंगे. यदि आवश्यक हुआ, तो भूमि पर कब्जा करने वालों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए गहन जांच का आदेश दिया जाएगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्हें उन अधिकारियों का मौन संरक्षण और समर्थन प्राप्त था जिनसे सार्वजनिक संपत्तियों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती थी।'

निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध जारी रहेगा

उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर को अदालत ने सभी निजी व्यक्तियों को कथित रूप से अतिक्रमित भूमि का हस्तांतरण करने या किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन करने से भी रोक दिया था. अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति न दी जाए।

सोमवार को पीठ ने कहा कि ये निर्देश लागू रहेंगे.

राज्य ने बताया कि उसने अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और यह अभियान जारी रहेगा. उसने यह भी कहा कि भारी हिंसा के कारण अधिकारी अभियान के दौरान कुछ क्षेत्रों तक नहीं पहुंच सके. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते कि आप आगे क्या करेंगे... हम देखेंगे कि अतीत में आपका आचरण कैसा रहा है. आज, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में, आप सब कुछ पलटना चाहते हैं. अतीत में आप क्या करते रहे हैं?' यह मामला ऋषिकेश में लगभग 2,866 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे 1950 में भूमिहीन परिवारों को आवंटित करने के लिए पशुलोक सेवा समिति को पट्टे पर दिया गया था. इसके बाद 1984 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने यह आवंटन वापस ले लिया था और ये ज़मीन सरकार के पास वापस आ गई थी. हालांकि, इसके बावजूद इस पर दशकों तक निजी कब्जा जारी रहा है।

तेल, ताकत और तख्तापलट: लोकतंत्र की स्थापना या अमेरिका की नव-औपनिवेशिक चाल

अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के विरुद्ध अपनाई गई नीतियों और कार्रवाइयों को यदि समग्र वैश्विक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल किसी एक देश के साथ द्विपक्षीय टकराव का मामला नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसे अनेक विद्वान और विश्लेषक नव-औपनिवेशिक युग का नया रूप मानते हैं। इस नए दौर में प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद के स्थान पर आर्थिक दबाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, सैन्य धमकियाँ, सूचना युद्ध और अंतराष्ट्रीय संस्थाओं की चयनात्मक अवहेलना के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। वेनेजुएला के संदर्भ में अमेरिका पर यह आरोप लंबे समय से लगता रहा है कि उसने वहाँ की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के साधनों का उपयोग किया। इसमें कठोर आर्थिक प्रतिबंध, राजनयिक अलगाव, विपक्षी गुटों को अंतराष्ट्रीय वैधता प्रदान करना और सत्ता परिवर्तन को खुले अथवा छिपे रूप में प्रोत्साहित करना शामिल है। कुछ मीडिया रिपोर्टों और राजनीतिक विश्लेषणों में यह दावा भी सामने आया कि अमेरिका समर्थित अभियानों का उद्देश्य राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाना या उन्हें अंतराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के लिए मजबूर करना था, जिसे वेनेजुएला की सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। आलोचकों का तर्क है कि यह व्यवहार उस औपनिवेशिक मानसिकता की आधुनिक अभिव्यक्ति है, जिसमें शक्तिशाली देश यह मान लेते हैं कि उन्हें यह अधिकार है कि वे यह तय करें कि किस देश में कौन शासन करेगा और किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था 'वैध' मानी जाएगी। यह दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतराष्ट्रीय कानून की उस मूल भावना के विपरीत है, जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार्य मानती है। वेनेजुएला पर लगाए गए एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर भी यही प्रश्न उठता है, क्योंकि ये प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की औपचारिक स्वीकृति के बिना लागू किए गए। इसके बाद वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अमेरिका के प्रभाव का उपयोग कर अन्य देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी इन्हें मानने का दबाव डाला गया। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अंतराष्ट्रीय नियमों का सम्मान तभी आवश्यक समझा जाता है, जब वे अमेरिका के रणनीतिक और आर्थिक हितों के अनुकूल हों। आलोचकों के अनुसार इन प्रतिबंधों का सबसे गहरा प्रभाव वेनेजुएला की राजनीतिक सत्ता पर नहीं, बल्कि वहाँ की आम जनता पर पड़ा। तेल निर्यात, बैंकिंग लेनदेन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने से वेनेजुएला में आर्थिक और मानवीय संकट और अधिक गहरा गया। यह स्थिति उस दावे के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है कि प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल लोकतंत्र की बहाली या मानवाधिकारों की रक्षा करना था। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका की भूमिका इसलिए भी विवादास्पद हो जाती है, क्योंकि वह स्वयं को नियम-आधारित अंतराष्ट्रीय व्यवस्था का संरक्षक बताता है, किंतु व्यवहार में वह उन्हीं नियमों को तोड़ता हुआ दिखाई देता है।

यही दोहरा मानदंड वैश्विक दक्षिण के देशों में गहरे असंतोष और अविश्वास को जन्म देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे वैश्विक शांति और सुरक्षा का सर्वोच्च मंच माना जाता है, वेनेजुएला जैसे मामलों में हाशिये पर धकेल दी जाती है। अमेरिका अपने वीटो-आधारित प्रभाव, सैन्य शक्ति और आर्थिक दबाव के माध्यम से यह दिखाता है कि वास्तविक शक्ति संस्थागत सहमति में नहीं, बल्कि बल और प्रभाव में निहित है। आलोचक यह भी कहते हैं कि वेनेजुएला को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, ताकि अन्य देशों को यह संदेश दिया जा सके कि यदि उन्होंने अमेरिकी नीतिगत ढाँचे से अलग रास्ता अपनाया, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह रणनीति औपनिवेशिक युग की दंडात्मक कार्रवाइयों की आधुनिक पुनरावृत्ति जैसी प्रतीत होती है। वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार और उसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह आरोप और मजबूत हो जाता है कि अमेरिका की वास्तविक रुचि लोकतंत्र या मानवाधिकारों से अधिक संसाधनों और क्षेत्रीय प्रभुत्व में रही है। इतिहास यह भी दिखाता है कि अमेरिका अपने रणनीतिक सहयोगियों के मानवाधिकार उल्लंघनों पर अक्सर चुप्पी साध लेता है, जबकि विरोधी या स्वतंत्र नीति अपनाने वाले देशों के मामलों में वही मुद्दे आक्रामक हस्तक्षेप का आधार बन जाते हैं। यही चयनात्मक नैतिकता अमेरिका की वैश्विक विश्वसनीयता को कमजोर करती है। वेनेजुएला के प्रकरण ने अमेरिका की अंतराष्ट्रीय छवि को भी गहरा आघात पहुँचाया है। शीत युद्ध के बाद जिस अमेरिका ने स्वयं को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक और वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया था, वह अब अनेक देशों की दृष्टि में एक ऐसी शक्ति बनता जा रहा है जो अपने घटते प्रभाव और उभरते बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के भय से प्रेरित होकर अधिक आक्रामक और हस्तक्षेपवादी नीति अपना रही है। रूस, चीन और अन्य उभरती शक्तियों के बढ़ते प्रभाव ने अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे एकध्रुवीय वर्चस्व को चुनौती दी है। वेनेजुएला जैसे मामलों में कठोर रुख अपनाकर अमेरिका यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह अब भी वैश्विक नियम तय करने की क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया में अंतराष्ट्रीय संस्थानों की प्रासंगिकता और वैधता को नुकसान पहुँचता है। जब सबसे शक्तिशाली देश स्वयं संयुक्त राष्ट्र के ढाँचे को नजरअंदाज करता है, तो अन्य देशों के लिए भी अंतराष्ट्रीय कानून का पालन एक वैकल्पिक विकल्प बन जाता है, न कि बाध्यकारी दायित्व। वेनेजुएला में कथित सत्ता परिवर्तन अभियानों और दबाव की राजनीति ने वहाँ के आंतरिक संकट को सुलझाने के बजाय और अधिक जटिल बना दिया। बाहरी हस्तक्षेप ने राजनीतिक संवाद और राष्ट्रीय सुलह की संभावनाओं को कमजोर किया और समाज को गहरे ध्रुवीकरण की ओर धकेल दिया। यदि अमेरिका वास्तव में अंतराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के प्रति ईमानदार होता, तो वह एकतरफा कार्रवाई के बजाय संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से बहुपक्षीय समाधान और निष्पक्ष मध्यस्थता को प्राथमिकता देता। ऐसा न करके उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक संस्थान उसके लिए साधन हैं, लक्ष्य नहीं।

वेनेजुएला का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक दक्षिण के उन ऐतिहासिक अनुभवों से मेल खाता है, जहाँ औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने हितों के लिए स्थानीय शासन, अर्थव्यवस्था और समाज को नियंत्रित किया। आज वही नियंत्रण नए रूपों में, जैसे प्रतिबंध, ऋण, राजनीतिक दबाव और सूचना युद्ध के माध्यम से दोहराया जा रहा है। इसी कारण अमेरिका की नीतियों को नव-औपनिवेशिक विश्व व्यवस्था के विस्तार के रूप में देखा जाता है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचना केवल अमेरिका-विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बुनियादी प्रश्न से जुड़ी है कि क्या आज की अंतराष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में समानता, संप्रभुता और कानून के सिद्धांतों पर आधारित है, या फिर यह अब भी शक्ति, दबाव और चयनात्मक नैतिकता से संचालित होती है। जब तक इस असंतुलन को दूर नहीं किया जाता, तब तक वेनेजुएला जैसे उदाहरण वैश्विक राजनीति में बार-बार उभरते रहेंगे और विश्व व्यवस्था की वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े करते रहेंगे और विश्व व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति बनी रहेगी।

आदित्य वर्मा, शोधार्थी

संपादकीय

बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं की साझा हुंकार,सत्ता, लोकतंत्र और महाराष्ट्र की अस्मिता की जंग

बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी के आगामी चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय बाद ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि आम जनता का भी ध्यान खींचा। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक साथ मंच पर दिखे और संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए सत्ताधारी गठबंधन, चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया। यह केवल दो नेताओं की साझा उपस्थिति भर नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई धुरी आकार ले सकती है, खासकर उस समय जब बीएमसी जैसे देश के सबसे समृद्ध नगर निकाय का चुनाव नजदीक है।

उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में जिस तरह 'लोकतंत्र से झुंडशाही' की ओर देश के बढ़ने का आरोप लगाया, वह बयानबाजी से कहीं आगे की बात थी। उन्होंने कहा कि पहले वोट चोरी होते थे, अब उम्मीदवार चुराए जा रहे हैं। यह टिप्पणी सीधे-सीधे दलबदल, दबाव की राजनीति और सत्ता के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है। उद्धव ठाकरे का यह आरोप कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं पर गहरे सवाल खड़े करता है। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया तंज और चुनाव आयोग को दी गई खुली चुनौती, यह दर्शाती है कि विपक्ष अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक मुद्रा में है।

राज ठाकरे ने अपने अंदाज में भाजपा पर पलटवार करते हुए दोहरे मापदंडों का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ भाजपा सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में इसी तरह की परिस्थितियों पर वही पार्टी चुप है। राज ठाकरे का यह सवाल सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में सिद्धांत और सुविधा के बीच बढ़ती खाई को भी उजागर करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती और जो यह मान बैठे हैं कि वे हमेशा सत्ता में रहेंगे, उन्हें इतिहास से सबक लेना चाहिए।

राज ठाकरे का यह कहना कि महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार की राह पर ले जाया जा रहा है, भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अहम है। महाराष्ट्र हमेशा से सामाजिक सुधार, औद्योगिक विकास और प्रगतिशील राजनीति का केंद्र रहा है। यदि यहां की राजनीति में भय, दमन और अवसरवाद हावी होता है, तो यह केवल राज्य ही नहीं, पूरे देश के लिए नकारात्मक संकेत होगा। राज ठाकरे ने विचारधाराओं के बार-बार बदलने को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया, और यह टिप्पणी मौजूदा दौर के राजनीतिक पलायन पर सटीक बैठती है।

उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भी तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समुद्र में पूजा करने और पौराणिक उपलब्धियों से खुद को जोड़ने के बावजूद आज तक शिवाजी महाराज की प्रतिमा सामने नहीं आई। यह बयान प्रतीकात्मक राजनीति और वास्तविक कामकाज के अंतर को उजागर करता है। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक हैं और उनके नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन उनके आदर्शों के अनुरूप शासन करना कहीं अधिक कठिन। चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर उद्धव ठाकरे के आरोप इस पूरी प्रेस वार्ता का सबसे गंभीर हिस्सा रहे। रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग और विधानसभा अध्यक्ष पर उम्मीदवारों व मतदाताओं को धमकाने का आरोप, संवैधानिक मर्यादाओं को लेकर गहरी चिंता पैदा करता है। यदि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग निष्पक्षता छोड़कर सत्ता पक्ष के हित में काम करने लगें, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होना स्वाभाविक है। उद्धव ठाकरे का यह कहना कि विधानसभा अध्यक्ष को निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, राजनीति में जवाबदेही की मांग को सामने लाता है।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रश्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की भूमिका और कर्तव्य को लेकर उठता है। राज ठाकरे की पार्टी लंबे समय से मराठी अस्मिता, स्थानीय रोजगार और मुंबई की पहचान के मुद्दों पर मुखर रही है। बीएमसी चुनाव में मनसे की भूमिका केवल सीटों की गणित तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि ठाकरे बंधुओं की यह साझा हुंकार महज सत्ता विरोधी बयानबाजी बनकर रह जाती है, तो इसका असर सीमित होगा। लेकिन यदि मनसे अपने मूल एजेंडे को लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और स्थानीय स्वशासन की मजबूती से जोड़ती है, तो यह गठजोड़ महाराष्ट्र की राजनीति में सार्थक बदलाव ला सकता है।

मनसे का कर्तव्य है कि वह भावनात्मक मुद्दों के साथ-साथ प्रशासनिक और शहरी समस्याओं पर भी ठोस दृष्टिकोण रखे। मुंबई आज बुनियादी ढांचे, आवास, परिवहन, पर्यावरण और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। बीएमसी चुनाव केवल सत्ता का नहीं, बल्कि शहर के भविष्य का चुनाव है। मनसे यदि उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर एक ऐसा संयुक्त घोषणापत्र पेश करती है, जो केवल विरोध नहीं बल्कि समाधान भी दे, तो यह मतदाताओं के बीच भरोसा पैदा कर सकता है। ठाकरे बंधुओं की यह साझा उपस्थिति अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़ने का संकेत भी देती है। कभी एक ही राजनीतिक विरासत से निकले ये दोनों नेता वर्षों तक एक-दूसरे के कट्टर विरोधी रहे। ऐसे में उनका एक मंच पर आना यह दर्शाता है कि परिस्थितियां किस तरह राजनीति को नए समीकरण गढ़ने पर मजबूर करती हैं। सवाल यह है कि क्या यह एक स्थायी राजनीतिक समझ की शुरुआत है या केवल चुनावी मजबूरी का परिणाम।

बीएमसी चुनाव से पहले उठी यह सियासी हलचल साफ संकेत देती है कि आने वाले दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए निर्णायक होंगे। सत्ता पक्ष पर लगे आरोप, लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल और विपक्ष की एकजुटता की कोशिश, यह सब मिलकर चुनाव को बेहद रोचक और तनावपूर्ण बना रहे हैं। ठाकरे बंधुओं की साझा हुंकार केवल एक प्रेस वार्ता नहीं, बल्कि यह संदेश है कि महाराष्ट्र की राजनीति में असंतोष गहराता जा रहा है। अंततः यह फैसला जनता के हाथ में होगा कि वह इस साझा हुंकार को परिवर्तन की उम्मीद के रूप में देखती है या इसे एक और राजनीतिक प्रयोग मानकर खारिज कर देती है। लेकिन इतना तय है कि बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निकाय का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह लोकतंत्र, संस्थाओं की साख और महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय करने की लड़ाई बन चुका है।

कांतिलाल मांडोत

आमजन में उम्मीद की लौ जलाने में कामयाब रही मोदी सरकार

आजादी के 77 साल में यदि भारत के विकास क्रम की समीक्षा की जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 वर्षों का कार्यकाल यकीनन पिछले साढ़े छह दशक पर भारी है। मोदी सरकार ने देश के विकास की एक नयी लकीर खींची है। नरेन्द्र मोदी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिये समर्पित रहा है। यह समय अनूठा, अद्भुत और अकल्पनीय है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व में मान, सम्मान और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा देश की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान की यात्रा है। इसमें एक ओर भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है, देश का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है और भारत अब डिफेंस इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। वहीं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सम्मान का मंत्र दिया। उन्होंने इन्हीं चार स्तंभों के समग्र विकास से वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण का मार्ग बताया।

प्रधानमंत्री जी की नीतियों और निर्णयों ने नये आत्मनिर्भर भारत निर्माण को गति दी है। 11 वर्ष पूर्व पूर्व पीएम मोदी ने संसद की सीढ़ियों को नमन करके जो संकल्प व्यक्त किये थे, उनमें उनकी भावी यात्रा के साथ नये भारत निर्माण के संकेत भी थे। उन्होंने निरंतर अपने संकल्पों की सिद्धि के साथ देश को आगे बढ़ाया है और राष्ट्र तथा समाज के उत्थान के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, भारत में नागरिकता कानून (सीएए) बनाने, तीन तलाक जैसे अमानवीय कानून को समाप्त करने, वक्फ संपत्ति का मुस्लिम समाज के कल्याण में उपयोग के लिए वक्फ संशोधन विधेयक कानून लाने जैसे निर्णय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति से ही संभव हुए हैं। उनका दृढ़ संकल्प सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भी दिखाई दिया। बालाकोट के बाद ऑपरेशन सिंदूर से भारत के सामर्थ्य को पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में बहनों के सामने आतंकियों ने उनका सिंदूर मिटाया था, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित कर दिया कि यह नया भारत है जो राष्ट्र के सम्मान, नागरिकों की सुरक्षा और मानवता के लिए घर में घुसकर भी मारना जानता है।

पीएम मोदी के कार्यकाल की यह समृद्ध यात्रा राष्ट्र की उमति, आधारभूत समस्याओं के निराकरण और वैश्विक छवि के उत्थान की रही है। देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क अम्र, 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पका घर, हर घर में शौचालय, 15.6 करोड़ से अधिक भरों में नल से जल, 10 करोड़ से अधिक मरों में उज्वला योजना से गैस कनेक्शन और गांवों को रोशन किया है। उनके स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छता एवं साफ सफाई में जुट गया। प्रधानमंत्री जी ने 'सबका साथ, सचका विकास और सबका विश्वास' का उद्घोष किया। उनकी नीतियों में अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की अवधारणा है। सबके स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए 'आयुष्मान भारत' अभियान चलाया। इसमें 9 करोड़ से अधिक लोगों का मुफ्त उपचार हुआ है।

सत्तर वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को भी निःशुल्क उपचार मिला है। 16 हजार से अधिक जन औषधि केन्द्रों से सस्ती और अच्छी दवाएं उपलब्ध करवाई है। कोरोना काल में देशवासियों को आपदा में अवसर का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण का संकल्प दिया और देशवासियों को स्वदेशी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई। इस भारतीय वैक्सीन को दुनिया के कई देशों ने भी स्वीकारा। उन्होंने श्रृंखलाबद्ध लोक एवं जन कल्याण कारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के समग्र विकास की समुचित व्यवस्था की। जनधन योजना से 55 करोड़ से अधिक लोगों को वित्तीय धारा से जोड़ा गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से गरीवों को 44 लाख करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। पीएम स्वनिधि और स्ट्रीट वेंडर से रेहड़ी-पटरी के व्यवसायियों को आधार दिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी, युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए, नई शिक्षा नीति के साथ 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास और 1.6 लाख से अधिक स्टार्टअप्स शुरू कर युवाओं को विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिये भागीदार बनाया है। मध्यप्रदेश ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को अमल में लाया और युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार तथा स्व-रोजगार के लिये अनंत संभावनाए विकसित की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 7.7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा से अप्रदाताओं को संबल मिला है। महिलाओं की सुरक्षा के उपाय, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। देशभर में लगभग 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। देश में 90 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के माध्यम से 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी।

प्रधानमंत्री जी की आर्थिक नीतियों, विशेषकर नोटबंदी जिससे कदाचार पर नियंत्रण हुआ, डिजिटलाइजेशन और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से ऑनलाइन लेनदेन का चलन बढ़ा। इन सभी नीतियों ने आर्थिक विकास के निर्णयों को सबल किया और भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। प्रधानमंत्री जी ने विकास के साथ विरासत का आह्वान किया है। विरासत को सहेजने के लिए उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास और पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य आरम्भ किया तथा इसे धार्मिक पर्यटन से जोड़ा। लोगों का अपनी विरासत के प्रति सम्मान बड़ने के साथ पर्यटकों की संख्या भी बड़ी है। नमामि गंगे योजना से पवित्र नदियों की सफाई अभियान के साथ जल संरक्षण की परम्परा विकसित हो रही है। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का आह्वान किया था जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) के वैज्ञानिकों से स्वयं चर्चा की और आवश्यक बजट तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। इसका परिणाम यह है कि भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान तकनीक विश्व में अग्रणी बनी और चंद्रमा के दक्षिणी व पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। कनेक्टिविटी से विकास को गति प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री जी ने सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार किया।

23 शहरों में मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति, बंदरगाह, हवाई मार्ग, हाई स्पीड कॉरिडोर निर्माण के लक्ष्य को स्वरूप प्रदान किया है। अटल टनल और दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब आकार ले चुका है। पीएम मोदी का संकल्प है कि स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी वर्ष 2047 तक भारत को 35 ट्रिलियन डॉलर की पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था बनाना और विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना है।

इस संकल्प की पूर्ति में सभी प्रदेश सहभागी बनने के लिये प्रतिबद्ध है। देश तमाम दुनिया के बदलते समीकरणों के बीच भी अधिक स्वायत्तवता और सम्मान के साथ अंतरराष्ट्रीय जगत में अपनी गरिमा को बनाए रखने में कामयाब रहा है ।वहीं आम आदमी में सरकार उम्मीद की एक लौ जगाने में भी कामयाब रही है यह स्वयं मे बड़ी बात है क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की संकल्प शक्ति ही सरकार की ताकत है।

मनोज कुमार अग्रवाल

सौंदर्य की नई भाषा: जब महिलाएं बोलती हैं,'मेरा शरीर, मेरे नियम'

असली सुंदरता: नाप, रंग या सांचे में नहीं, आत्म-स्वीकृति में

असली सुंदरता की नई भाषा: आत्म-विश्वास और सशक्त पहचान

एक लड़की आईने के सामने खड़ी है। समाज कहता है- पतली हो जाओ, गोरी बनो, परफेक्ट बनो। लेकिन वह मुस्कुराती है और कहती है, 'मेरा शरीर, मेरे नियम!' यह नारा आज लाखों महिलाओं की आवाज बन चुका है। बॉडी पॉजिटिविटी आंदोलन ने महिलाओं को सिखाया है कि सुंदरता का मतलब सिर्फ एक सांचे में फिट होना नहीं। यह आंदोलन आत्म-सम्मान, स्वीकृति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। बॉलीवुड की चकाचौंध से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया तक, महिलाएं अब अपने शरीर को शर्म की बजाय गर्व का विषय बना रही हैं। भारत में यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है, जहां सदियों से महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण की कोशिशें हुई हैं। अब समय आ गया है कि हम इस बदलाव को समझें और अपनाएं।

बॉडी पॉजिटिविटी का मूल अर्थ है हर प्रकार के शरीर को बिना शर्त स्वीकार करना - चाहे वह दुबला हो, स्थूल, गोरा, सांवला या कोई भी आकार-प्रकार। यह आंदोलन 1960 के दशक में अमेरिका में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट से शुरू हुआ, और सोशल मीडिया ने इसे वैश्विक बनाया। भारत में लंबे समय तक बॉलीवुड और विज्ञापनों ने 'जीरो फिगर' को आदर्श बनाया, जिससे अनगिनत महिलाएं बॉडी इमेज इश्यूज और ईटिंग डिसॉर्डर की शिकार हुई। लेकिन अब महिलाएं कह रही हैं कि उनका शरीर उनका निजी क्षेत्र है, कोई और तय नहीं करेगा कि वह कैसी दिखेंगी। सोशल मीडिया पर प्लस-साइज इन्फ्लुएंसर्स अपनी अनफिल्टर्ड तस्वीरें शेयर कर रही हैं, और लाखों महिलाएं इससे प्रेरित होकर खुद को प्यार करना सीख रही हैं। यह बदलाव सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि गहरे मानसिक परिवर्तन का है।

भारत में बॉडी पॉजिटिविटी को नई दिशा और मजबूती देने में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम रही है। अनेक महिलाएं अपने डिजिटल मंचों पर बिना झिझक अपनी निजी कहानियां साझा कर रही हैं। वे खुलकर बताती हैं कि बचपन में 'मोटी' या 'काली' जैसे शब्दों से मिले तानों ने उनके मन पर कितने गहरे घाव छोड़े, और उस पीड़ा से निकलकर आत्मविश्वास तक पहुंचना कितना कठिन रहा। इसी ईमानदारी ने लाखों महिलाओं को खुद को स्वीकार करने की हिम्मत दी है। फैशन इंडस्ट्री में भी यह बदलाव साफ दिखाई देता है, जहां अब रैंप पर विविध शरीर आकारों की मौजूदगी बढ़ी है। कपड़ों के बाजार में भी सोच बदली है और विस्तृत साइज विकल्प सामने आ रहे हैं। महिलाएं अब साफ शब्दों में कह रही हैं कि वे अपने शरीर के अनुसार कपड़े चाहती हैं, न कि कपड़ों के अनुसार खुद को बदलना। यही सोच उन्हें मानसिक स्वतंत्रता दे रही है, जहां बॉडी शेमिंग का डर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। 'मेरा शरीर, मेरे नियम' का नारा केवल वजन या शरीर के आकार तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह महिलाओं के समग्र अधिकारों की मुखर अभिव्यक्ति बन चुका है। इसमें अपने कपड़े खुद चुनने की आज़ादी है, अपने शरीर से जुड़े निर्णय स्वयं लेने का साहस है और प्रजनन से जुड़े फैसलों पर अधिकार की स्पष्ट मांग भी शामिल है। भारतीय समाज में, जहां परिवार और रिश्तेदार अक्सर महिलाओं के शरीर पर टिप्पणी करने या उसे नियंत्रित करने का अधिकार अपने हाथ में समझ लेते हैं, यह नारा एक सशक्त प्रतिरोध की तरह उभरता है। महिलाएं अब ऑनलाइन आलोचनाओं और ट्रोलिंग को चुपचाप सहने के बजाय आत्मविश्वास से जवाब दे रही हैं। डिजिटल मंचों पर शरीर के प्राकृतिक पहलुओं को सामान्य बताने की कोशिशें तेज़ हुई हैं। मध्य आयु की महिलाएं भी इस सोच से जुड़ रही हैं, जो लंबे समय तक चुप्पी ओढ़े रहीं। इससे नई पीढ़ी तक यह संदेश पहुंच रहा है कि सुंदरता किसी एक ढांचे में नहीं, बल्कि विविधता में अपनी असली पहचान पाती है।

इस आंदोलन के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। कई बार बॉडी पॉजिटिविटी को व्यावसायिक ब्रांड केवल प्रचार का साधन बना लेते हैं, जहां असली सामाजिक बदलाव पीछे छूट जाता है। कुछ महिलाएं जब अपनी फिटनेस यात्रा शुरू करती हैं, तो उन्हें ही यह कहकर निशाना बनाया जाता है कि वे आंदोलन की भावना के खिलाफ जा रही हैं। भारत में गोरेपन की क्रीमों, स्लिमिंग उत्पादों और डाइट उद्योग का प्रभाव आज भी गहरा और व्यापक है। इसके बावजूद सकारात्मक परिवर्तन इन बाधाओं से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरा है। स्कूलों और कॉलेजों में अब इस विषय पर खुली चर्चाएं होने लगी हैं। माताएं अपनी बेटियों को यह सिखा रही हैं कि हर शरीर अलग, अनोखा और सुंदर होता है। यह आंदोलन नारीवादी सोच का अहम हिस्सा बन चुका है, जहां महिलाएं अपने शरीर की वास्तविक स्वामिनी बन रही हैं। इसका असर उनके करियर, रिश्तों और पूरे जीवन पर सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है।

बॉडी पॉजिटिविटी को जीवन में अपनाने के लिए बड़े प्रयास नहीं, बल्कि छोटे और सच्चे कदम ही पर्याप्त होते हैं। हर सुबह आईने में खुद को देखकर प्रशंसा करना आत्मस्वीकृति की शुरुआत हो सकती है। सोशल मीडिया पर उन्हीं मंचों से जुड़ना जरूरी है जो सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। व्यायाम को सजा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और खुशी का माध्यम बनाना चाहिए। दोस्तों और परिवार के साथ शरीर को लेकर खुलकर बातचीत करना भी बेहद जरूरी है। भारत में यह आंदोलन अब महानगरों से निकलकर गांवों तक पहुंच चुका है, जहां महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में भी पूरा आत्मविश्वास महसूस कर रही हैं। विभिन्न अभियानों के माध्यम से यह सोच और मजबूत हो रही है। महिलाएं यह समझने लगी हैं कि उनका शरीर सम्मान और स्नेह का पात्र है, आलोचना का नहीं। यह परिवर्तन समाज को अधिक समावेशी, संवेदनशील और मानवीय बना रहा है।

'मेरा शरीर, मेरे नियम' सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि यह एक पूर्ण क्रांति बन चुका है। यह महिलाओं को सदियों से उनके ऊपर थोपे गए शर्म और सामाजिक दबाव से मुक्त कर रहा है। भारतीय समाज में, जहां सौंदर्य के मानक हमेशा सख्त और कठोर रहे हैं, यह आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साबित हो रहा है। हर महिला को यह याद रखना चाहिए कि वास्तविक सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और आत्म-स्वीकृति में निहित होती है। समाज बदल रहा है, लेकिन हमें भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अगली बार जब कोई आपके शरीर पर टिप्पणी करे, तो गर्व के साथ कहें - मेरा शरीर, मेरे नियम! यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हर महिला खुद को पूरी तरह अपनाने और सम्मान देने के लिए स्वतंत्र न हो जाए। इसमें शामिल होकर, खुद से प्रेम करना और दूसरों को प्रेरित करना न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक बदलाव की भी जीत है।

कृति आरके जैन

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

विधानसभा की मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान शुरू

बलरामपुर/उतरौला। विधानसभा की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू हो गया है। इसके तहत तहसील में बने निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसमें मतदाता सूची में दर्ज नामों को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज लिए जाएंगे। एसडीएम अभय सिंह ने बताया कि यह कार्य सूची को सही ढंग से तैयार करने के लिए किया जा रहा है। बताया कि जिनका नाम मतदाता सूची में एक जनवरी 1987 से पूर्व दर्ज है, उन मतदाताओं को केवल एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। उन्हें 2003 की मतदाता सूची के साक्ष्य भी अपलोड करना होगा। सूची का मिलान 2003 की सूची से किया जा रहा है। अभी मिलान की प्रक्रिया ही की जानी है। बताया कि जिन मतदाताओं का जन्म 1987 से पूर्व हुआ हुआ है और 2003 की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है। उन मतदाताओं को जन्म प्रमाणपत्र व जन्मस्थान को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज लगाना होगा।

जिन मतदाताओं का जन्म 2004 के बाद हुआ उन्हें मतदाता सूची में जन्मतिथि व जन्मस्थान को प्रमाणित करने के लिए पिता और माता का प्रमाणपत्र देना होगा। मतदाता पुनरीक्षण में सरकार द्वारा निर्गत पेंशन, बोर्ड या विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल आदि साक्ष्य के रूप शामिल किए जाएंगे। एसडीएम ने बताया कि जल्द ही घर-घर अभियान चलेगा। अभी सूची का मिलान किया जा रहा है।

सिद्धार्थनगर- विद्यालय स्तर की गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता संपन्न हुई

सिद्धार्थनगर। जिलेमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6, 7 व 8 की विद्यालय स्तर की गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता सकुशल संपन्न हुई। इस अवसर पर नोडल प्रवक्ता पंकज कुमार ने बताया कि विद्यालय स्तर पर गणित ओलंपियाड की प्रतियोगिता को संपन्न करने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी, एआरपी गणित, एआरपी विज्ञान, प्रधानाध्यापक/इंचार्ज प्रधानाध्यापक का विशेष योगदान रहा। प्रत्येक विद्यालय से दो छात्रों का चयन किया जाएगा तथा ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता में 10 छात्रों का चयन किया जाएगा जो जनपद स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जनपद स्तर पर 5 बच्चों का चयन किया जाएगा। नोडल प्रवक्ता पंकज कुमार ने चार विद्यालय पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय सोनखर, बॉसी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय सूपाराजा, बॉसी, कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय बसडिलिया, नौगढ़ , पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय मधुबेनिय, बर्डपुर का निरीक्षण किया। नोडल प्रवक्ता पंकज कुमार ने यह भी बताया कि प्रतियोगिता में कुल 30 प्रश्न थे । कक्षा 5 से 7 तक के स्तर के थे। विद्यालय स्तर पर व्हाइट बोर्ड/ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नपत्र लिखा गया जबकि आगे के स्तर के लिए प्रश्नपत्र लिखित रूप में दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गणित ओलंपियाड की प्रतियोगिता छात्रों की गणितीय प्रतिभा और तर्क कौशल को बढ़ावा देने तथा गणित विषय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

पशुओं को हरा चारा, भूसा, व स्वच्छ पानी की व्यवस्था उपलब्ध रखें- सीडीओ

सिद्धार्थनगर। जिले के भनवापुर ब्लाक क्षेत्र के महतिनिया खुर्द स्थित शिव नंदी गौशाला का शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह ने औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान गौशाला परिसर में 85 गोवंशीय पशु पाए गए। सीडीओ ने गौशाला में पशुओं की देखभाल, चारे-पानी की व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने गोशाला में पशुओं की बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सीडीओ ने सचिव व ग्राम प्रधान को निर्देशित किया कि पशुओं को नियमित रूप से हरा चारा, भूसा व साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि गौशाला क्षेत्र में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए ताकि पशुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।इसके साथ ही उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण,टीकाकरण व दवा वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया। सीडीओ ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गौशालाओं का संचालन पारदर्शी और बेहतर तरीके से होना चाहिए ताकि बेसहारा पशुओं को उचित आश्रय व देखभाल मिल सके।इस दौरान बीडीओ विनोद मणि त्रिपाठी,लालजी शुक्ला,राधे रमण, लाली, भोलू, झब्बू आदि मौजूद रहे।

सामुदायिक शौचालयों में करोड़ों का खेल!

● कागज़ों में सफाई, ज़मीन पर ताले – हर महीने 9000 रुपये का फर्जी भुगतान जारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलरामपुर। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर जिले में भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो सुनकर जनता हैरान है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सामुदायिक शौचालय संचालन अब "सफाई नहीं, सफाई के नाम पर कमाई" का जरिया बन चुकी है। जिले में बने अधिकांश सामुदायिक शौचालय महीनों से बंद पड़े हैं, लेकिन हर महीने 9000 रुपये का भुगतान स्वयंसहायता समूह की महिलाओं के खातों में जारी है। आश्चर्य की बात यह है कि ये भुगतान तब भी हो रहे हैं जब एक भी शौचालय सुचारू रूप से संचालित नहीं है।

ज़मीन पर सच्चाई — जर्जर भवन, टूटी टंकी, उगी झाड़ियां

गांवों में जाकर हकीकत देखने पर साफ़ दिखता है कि शौचालयों के दरवाजों पर ताले लटक रहे हैं, पानी की सप्लाई महीनों से बंद है और कई जगह दीवारें टूट चुकी हैं। कहीं-कहीं तो शौचालय कूड़ा फेंकने की जगह बन चुके हैं।ग्रामीणों ने बताया कि कई शौचालयों की चाबियां किसी के पास नहीं हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। फिर भी कागज़ों में दिखाया जा रहा है कि सब कुछ "सुचारू रूप से संचालित" है।

ग्रामीण बोले — सफाईकर्मी को मिलता काम, तो बचता सरकारी धन

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शौचालय संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायत के सफाईकर्मियों को दिया गया होता, तो सरकार की करोड़ों रुपये की धनराशि बच सकती थी। ÷हर महीने 9000 रुपये किसी समूह को देने का क्या मतलब, जब शौचालय कभी खुले ही नहीं?" – एक ग्रामीण ने कहा।

भ्रष्टाचार की गंध — हर ब्लॉक में एक जैसी कहानी

सूत्रों के अनुसार, यह गड़बड़ी केवल एक-दो गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले में फैली हुई है। हर ब्लॉक में दर्जनों शौचालय बंद हैं, लेकिन भुगतान बराबर हो रहा है।अगर जिला प्रशासन ने इस पर निष्पक्ष जांच कराई, तो करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा होना तय है।

प्रशासन मौन, जनता आक्रोशित

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे "खुलेआम लूट का खेल" बताया है। उनका कहना है कि शासन की मंशा स्वच्छता लाने की थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत ने इस योजना की साख मिट्टी में मिला दी है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द जांच नहीं हुई, तो वे धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

जनता का सवाल — "कब जागेगा प्रशासन?"

"स्वच्छ भारत मिशन का मतलब था सफाई, न कि सफाई के नाम पर धन की बर्बादी। शौचालय अगर जनता के काम नहीं आए तो योजना का क्या अर्थ?" – यही सवाल अब गांव-गांव में गूंज रहा है।

दलित महिला व उसकी बेटी को जमीनी विवाद में लात घूसों व डंडों से बेरहमी से पीटा

लालगंज, रायबरेली। कोतवाली क्षेत्र के नवरंग सिंह का पुरवा मजरे आलमपुर गांव में शुक्रवार को रास्ते की विवाद को लेकर चार लोगों ने एक महिला और उसकी बेटी को डंडे लात घुसो से जमकर पिटाई कर दी। तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एससी एसटी सहित मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव निवासिनी कृष्णा देवी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आरोपी उसके घर के सामने दरवाजा खोल रहे थे मना करने पर गाली गलौज शुरू कर दी। एतराज करने पर परमेश्वर यादव उनकी पत्नी शिव देवी बेटे पिंटू और भतीजे छोटू के साथ मिलकर उसे घर से खींचकर उसकी लात घूंसो, डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। बचाने आई उसकी बेटी को भी जमकर मारा पीटा। पीड़िता ने बताया कि मारपीट कि यह घटना उसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

तहसील समाधान दिवस सम्पन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद। सरोजिनी नायडू सभागार में एडीएम/सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। द्वमलहा निवासी ग्राम प्रधान दिनेश कुमार ने बताया गांव में राजकीय विद्यालय का निर्माण 7 वर्ष पूर्व हो चुका है। विद्यालय में न ही क्लास रूम में बच्चों की बैठने की व्यवस्था है और न ही आने-जाने का समुचित मार्ग है।विद्यालय में कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई बाउण्ड्री वाल भी नहीं है जिससे आवारा कुत्ते व जानवर विद्यालय में टहलते हैं।

बकि खेल कूद हेतु जमीन मौके पर उपलब्ध है फिर भी खेलकूद से बच्चे वंचित है स्कूल जाने के लिए रास्ता नही होने के कारण विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। क्योंकि विद्यालय में आवश्यक सुविधा नही होने के कारण मेरे ग्राम पंचायत के बच्चे अन्य विद्यालय जाते हैं। जिससे ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को काफी कष्ट की अनुभूति होती है। यूसुफ खा ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया मलिहाबाद से घंटाघर तक इलेक्ट्रिक बस सेवा है जिसके अंतर्गत मलिहाबाद और घंटाघर में यात्री सुविधाएं नदारत है बारिश में बसों के इंतजार में यात्री खुले में खड़े होकर भीग जाते है। यात्री हित मे बारिश और धूप से बचाव के लिए छाया का प्रबंध किया जाय।

रहीमाबाद के गदिया खेड़ा निवासी राजाराम ने कैथुलिया गौशाला से लिए गए पशु का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल से उनके खाते में पशु की देखभाल और चारे का पैसा नहीं आ रहा है ब्लॉक में शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।तहसील दिवस में एसडीएम अंकित कुमार,एसीपी सुजीत कुमार दुबे, तहसीलदार और अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रेमी के साथ फरार पत्नी तीन बच्चों संग दर-दर भटक रहा पति

महराजगंज कोतवाली। क्षेत्र के हलोर गांव निवासी अंशु नाई की पत्नी एक युवक के साथ घर छोड़कर फरार हो गई है। आरोप है कि महिला अपने तीन छोटे बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग भाग गई और अब अपने पति को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दे रही है। पीड़ित पति अंशु नाई ने बताया कि उसने कई बार स्थानीय कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पुलिसिया अनदेखी से परेशान अंशु अब न्याय की गुहार लेकर तहसील दिवस में अपने तीन मासूम बच्चों के साथ पहुँचा।

अंशु का कहना है कि उसकी पत्नी की हरकत से उसका परिवार टूट गया है और अब वह बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित है। उसने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसकी पत्नी को बरामद कर उसे न्याय दिलाया जाए और उसे धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

घर के गेट पर मिला दस घरों में चोरी करने व हत्या की धमकी भरा खूनी पत्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज रायबरेली। घर के गेट पर मिला चोरी और हत्या की धमकी भरा 'खूनी' पत्र, एक साथ 10 घरों को निशाना बनाने की धमकी से गांव में हड़कंप। पुलिस छानबीन में जुटी। महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के मोन गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब डाक विभाग में कार्यरत डाक बाबू रामकुमार के घर के सामने गेट पर एक धमकी भरा पत्र मिला। हस्तलिखित इस पत्र में न सिर्फ एक साथ 10 घरों में चोरी करने की बात लिखी है, बल्कि इसका विरोध करने पर 15 लोगों की हत्या करने की भी खौफनाक धमकी दी गई है। यह सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए डाक बाबू रामकुमार ने कोतवाली पुलिस को बताया कि गुरुवार सुबह करीब दस बजे वह पत्नी सहित निमंत्रण में गए थे। घर में उसकी बहू ही अकेली थी। दोपहर करीब ढाई बजे जब उनकी बहू निशा ने घर के लान में लगे फूल के पेड़ पर्ची टंकी देखी तो मुहल्ले वालों को इसकी जानकारी दी। मिली पर्ची में लिखा है कि आज नौ बजकर तीस मिनट पर दस घर में चोरी करेंगे।जितना रखा बचाओ, उतना रखा लो।10 घर में चोरी करेंगे और 15 लोगों की मौत होगी आज। हम 10,000 हजार लोग हैं।"

करीब चार बजे निमंत्रण से वापस लौटे डाक-बाबू रामकुमार ने कोतवाली पुलिस से मिलकर मामले की लिखित शिकायत की है। उनका यह भी कहना है कि एक फेरी वाले ने उनके मुहल्ले में बाइक से कई चक्कर लगाएं है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने धमकी भरे पत्र को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह किसी की शरारत है। फिलहाल गांव में में गश्त बढ़ा दी गई है। और ग्रामीणों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

मिशन शक्ति अभियान के तहत अरों खेमाजितपुर में चौपाल

● पुलिस टीम ने दिया सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का मंत्र

महिलाओं ने बढ़ाया आत्मविश्वास, पुलिस से किया खुला संवाद- प्रधान विक्रम सिंह की रही अहम भूमिका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर(ब्यूरो)। कोतवाली देहात क्षेत्र की ग्राम पंचायत अरों खेमाजितपुर में मिशन शक्ति अभियान (फेज-5) के अंतर्गत एक विशेष चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल ने ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया संदेश देने के साथ ही उनमें आत्मविश्वास भी जगाया। ग्राम प्रधान विक्रम सिंह की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं, छात्राओं और अध्यापिकाओं की मौजूदगी ने माहौल को खास बना दिया। चौपाल में कोतवाली देहात पुलिस टीम महिला पुलिस कर्मियों के साथ पहुँची और उपस्थित महिलाओं को महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारियाँ साझा कीं। अपराध निरीक्षक राजबहादुर सिंह ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, लेकिन सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में, कार्यस्थल पर या सोशल मीडिया पर परेशान करे तो डरें नहीं, तुरंत सूचना दें – पुलिस तुरंत मदद करेगी। उन्होंने बताया कि आपकी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में शिकायत पेटिका रखवाई जाएगी। महिलाएं अपनी समस्या लिखकर उसमें डाल सकेंगी। सप्ताह में एक बार पुलिस टीम पेटिका खोलेगी, शिकायतों की वीडियोग्राफी होगी और तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

बड़ागांव चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक रामचंद्र यादव ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य हर महिला को निडर और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए – 1090 (वूमेन पॉवर लाइन), 182 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 108 (एंबुलेंस), 1098 (बाल संरक्षण), 1930 (साइबर हेल्पलाइन) आदि।

महिला कांस्टेबल आशा शर्मा ने महिलाओं को सरकार की योजनाओं और सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं ने भी खुलकर अपनी बातें रखीं और पुलिस अधिकारियों से सीधे संवाद किया। पंचायत सहायक ने महिलाओं का हौसला बढ़ाने वाली एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत की, जिस पर चौपाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के समापन पर ग्राम प्रधान विक्रम सिंह ने सभी अधिकारियों और उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसी चौपालें गांव की महिलाओं के आत्मविश्वास को और मजबूत करती हैं। चौपाल में हेड कांस्टेबल शिवपाल, कांस्टेबल मोनू कुमार, मोहम्मद अकरम, कपिल कुमार, नितिन शर्मा, विनीत कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और ग्रामीण मौजूद रहे।

ग्राम पंचायत दयालपुर में 32वां रामलीला मंचन व रावण दहन, हजारों दर्शक बने साक्षी

● ....52 फीट ऊँचे रावण के पुतले का दहन, 151 कन्याओं का पूजन और भव्य दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

निगोहां/लखनऊ। विजयदशमी पर्व के अवसर पर निगोहां क्षेत्र की ग्राम पंचायत दयालपुर में 32वां रामलीला मंचन और रावण दहन का भव्य आयोजन धूमधाम से सम्पन्न हुआ। इस दौरान 52 फीट ऊँचे रावण के पुतले का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण एकत्र हुए। असत्य पर सत्य की विजय के इस दृश्य ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा।

रामलीला मंचन के दौरान श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और मेघनाथ के प्रसंगों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मंचन में राम-रावण युद्ध, अंगद-रावण संवाद और हनुमान की वीरता के दृश्य देखकर लोग भाव-विभोर हो उठे। इस ऐतिहासिक आयोजन के बारे में मेला प्रबंधक रामभान सिंह ने बताया कि बीते 32 वर्षों से ग्राम पंचायत दयालपुर में रामलीला का आयोजन लगातार होता आ रहा है। यह आयोजन 28 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर विजयदशमी को सम्पन्न हुआ।

भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण लगभग 800 मीटर परिधि में बांस-बल्लियों से निर्मित विशाल दुर्गा पंडाल रहा। इसमें दर्शकों के लिए आकर्षक गुफाएं और झांकियां बनाई गईं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनीं। इसी पंडाल में रामलीला का मंचन हुआ और रावण दहन का आयोजन सम्पन्न हुआ। आयोजन के दौरान धार्मिक परंपराओं का भी पालन किया गया। 151 कन्याओं का पूजन कर उन्हें खीर-पूरी का भोग लगाया गया। सभी कन्याओं को ससम्मान भोजन कराया गया। वहीं अगले दिन ढोल-नगाड़ों और बाजों के साथ माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। रामलीला कमेटी के मेला अध्यक्ष रामभान सिंह, शैलेंद्र (शीलू) शुक्ला, प्रधान प्रतिनिधि शैलेन्द्र पाल, डॉ. अवधेश कुमार कश्यप, गुड्डू मिश्रा, सरजू प्रसाद, शुभम मिश्रा, आशीष मिश्रा, सुशील शुक्ला, नीरज सिंह, विकास विश्वकर्मा, सचिन चौधरी, मुकेश मधुकर, शिवम मिश्रा, रजनीकांत सैनी, प्रभाकांत सैनी, अजीत सैनी, पंकज सैनी, अनिल तिवारी, आर्यन सिंह, रिवान सिंह, उत्कर्ष साहू, बंटी साहू, सोनू धीमान, मनीष रावत, अंश भारती, होरीलाल साहू, मयंक शुक्ला, अंबुज मिश्रा, सुनील भारती, सतीश विश्वकर्मा, नीतीश शुक्ला सहित तमाम कलाकार और समिति के सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। इस भव्य आयोजन ने न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत किया बल्कि असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश भी जनमानस तक पहुंचाया।

रेलवे स्टेशन पर गंदगी देख डीआरएम ने अफसरों को लगाई कड़ी फटकार

● लालगंज रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में मिलेगी नई सूरत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) सुनील कुमार वर्मा ने शनिवार की शाम लालगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन परिसर में फैली गंदगी देखकर उन्होंने स्टेशन अधीक्षक और ईओडब्ल्यू उन्नाव के अफसर को कड़ी फटकार लगाई। डीआरएम ने प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, कंट्रोल रूम, शौचालय और कैंटीन तक का बारीकी से निरीक्षण किया। शौचालय और वाटर कूलर के आसपास जमा गंदगी देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। डीआरएम शाम करीब 4ः30 बजे विशेष निरीक्षण यान से प्लेटफार्म नंबर दो पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने करीब 40 मिनट तक पूरे परिसर का जायजा लिया। वह प्रधानमंत्री की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान साथ मौजूद चीफ इंजीनियर ऋषि कुमार यादव ने उन्हें प्रस्तावित बदलावों की जानकारी दी। योजना के तहत स्टेशन को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। प्लेटफार्म पर टीन शेड लगाए जाएंगे, विकलांग यात्रियों के लिए रैंप की सुविधा बनेगी, स्टेशन के दाईं ओर पार्किंग और बाईं ओर पार्क विकसित किया जाएगा। साथ ही स्टेशन पर वीआईपी गेट भी तैयार किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने गेट नंबर 72 बी का निरीक्षण किया। गेट पर आरोपी बनाने को लेकर मातहतों से चर्चा की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि गेट नंबर 71 बी पर आरोही बनाना संभव नहीं है। लेकिन बछरावां रोड रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से आरोबी बनाया जा सकता है।

व्यापार मंडल ने सौंपा ज्ञापन

डीआरएम के दौरे पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। इसमें आरसी ट्रेन चलाने की मांग की गई। साथ ही यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट सिस्टम शुरू करने, आरक्षण काउंटर का समय दो घंटे बढ़ाने, प्रतीक्षालय खोलने, शौचालय व पेयजल की उचित व्यवस्था कराने की मांग रखी गई।

डीआरएम ने आरसी ट्रेन के संबंध में बोर्ड को पत्राचार का आश्वासन दिया। यात्री सुविधाओं को जल्द बेहतर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मौके पर व्यापारी संगठन के पदाधिकारी मदन मिश्रा, रोहित सोनी, शिवम गुप्ता, मृत्युंजय बाजपेई, शीलू त्रिवेदी, कौशलेंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

एडीएम की अध्यक्षता में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस एसडीएम व सीओ रहे मौजूद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज रायबरेली। शासन की मंशा के अनुरूप फरियादियों की शिकायत को गंभीरता से ले मौके जांच कर नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें लापारवाही बर्दास्त नही की जायेगी ये उद्गार तहसील सभागार में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में एडीएम अमृता सिंह वित्त एवं राजस्व व्यक्त कर रही थी। एडीएम की अध्यक्षता में समाधान दिवस में कुल 40 शिकायते आई मौके पर 5 शिकायतो का निस्तारण किया गया।

आपको बता दें कि प्राप्त शिकायतो में सर्वाधिक शिकायत राजस्व 17 पुलिस 11, विकास 01 अन्य 11 प्रार्थना पत्र आए महराजगंज कस्बे के लोगो ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि कुछ स्थानों पर विद्युत पोल नही लगे हुए जिससे अंधेरा होने के कारण चोरी होने की संभावना रहती है जिस पर एडीएम ने संबधित को कार्यवाही के निर्देश दिए। शेष शिकायतो के निस्तारण के लिए सम्बन्धित को मौके पर जांच कर निस्तारण के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर एसडीएम गौतम सिंह क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार तहसीलदार मंजूला मिश्रा , नायब तहसीलदार उमेश चंद्र त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी वर्षा सिंह, राजस्व निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी, अहमद, आबिद अली, लेखपाल राजीव मिश्र, सुनील यादव, संतोष पटेल सहित सम्बन्धित थानों के उपनिरीक्षक मौजुद रहे।

बालिकाओं व महिलाओं को सुरक्षा के प्रति किया जा जागरूक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। मिशन शक्ति फेज- पांच के अंतर्गत शनिवार को उस्का बाजार विकास क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय परसा खुर्द में बालिकाओं व महिला अभिभावकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि एंटी रोमियो टीम की प्रभारी शाइस्ता खान ने बताया गया कि यदि कोई बालिका या महिला किसी प्रतिकूल स्थिति का सामना करे, तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए और सरकारी व सामाजिक सहायता तंत्र का उपयोग करना चाहिए। उन्होनें आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों 112 (इमरजेंसी सेवा), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1090 (वूमेन पावर लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्प लाइन), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) और 1076 (उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) की जानकारी दिया।साथ ही बालिकाओं और महिलाओं को उनकी सुरक्षा से जुड़े अधिकारों और तकनीकों की विस्तृत जानकारी देते व्यक्तिगत सुरक्षा पर चर्चा किया।

उन्होनें सिखाया कि विभिन्न सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारी ओपी मिश्र ने कहा कि इन कार्यकमों का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, अधिकारों और कानूनी प्रावधानों से जोड़ना है, ताकि वे आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन जी सकें। जनपदीय नोडल पशुपति दूबे ने मिशन शक्ति के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न सत्रों को आयोजित करने को लेकर दिए गए निर्देशों को बताया। कार्यक्रम में ब्लाक नोडल अनुराधा, एंटी रोमियो टीम की मधु ,श्रीप्रकाश चौरसिया, शिक्षक बालजीत , सुप्रिया, अर्चना, चंद्रजीत, अमित, अभिषेक आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

शासन ने बाल्मीकि जयंती का 7 अक्टूबर का अवकाश घोषित किया

मथुरा। प्रदेश के सामान्य प्रशासन अनुभाग के विशेष सचिव जुहेर बिन सगीर ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में निर्बन्धित अवकाशों की सूची के क्रमांक 25 पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 7 अक्टूबर (मंगलवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी दी है। इस दिन जनपद के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

जिला विकास अधिकारी को मातृ शोक

मथुरा, जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे की 94 वर्ष की माताश्री श्रीमती शांति देवेन्द्र खरे का इनके इलाहबाद स्थित आवास पर निधन हो गया। इनके निधन की खबर सुनकर विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों में शोक की लहर दोड़ गई। राजीव भवन में दो मिनट का मौन रखकर कर्मचारी एवं अधिकारियों ने श्रद्धाजलि अर्पित की।

उत्तर-पूर्वी जिले द्वारा बेला फार्म,शास्त्री पार्क, दिल्ली में दंगा-रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया

दिल्ली जिला उपायुक्त संदीप लाम्बा ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों की परिचालन दक्षता और तैयारियों का आकलन करने के लिए एक मॉक दंगा-रोधी अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित रहें और आपातकालीन स्थितियों के दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहें। मॉक ड्रिल के दौरान, वाटर कैनन, वज्र, विक्रांत और एम्बुलेंस की कार्यप्रणाली का गहन मूल्यांकन किया गया। गैसगन और एआरई जैसे उपकरणों को संभालने में कर्मचारियों की सतर्कता और दक्षता का भी परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल सुबह 08:00 बजे शुरू हुई, जिसमें 1 एसीपी,7 इंस्पेक्टर, उच्च और निम्न 162 अधीनस्थ कुल 170 इसके अतिरिक्त, अभ्यास के दौरान निम्नलिखित वाहन और उपकरण भी तैनात किए गए। वाटर कैनन, वज्र, विक्रांत, गैसगन और एमएसएल शामिल थे।

यमुना एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार दो युवकों की मौत

बैक पास बुक से हुई मृतक युवकों की पहचान

मथुरा। जनपद के थाना बलदेव क्षेत्र में शनिवार तड़के 4.45 पर यमुना एक्सप्रेस वे पर माइल स्टोन 140 पर दो बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, दोनों बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। एक व्यक्ति बुरी तरह से कुचल गया। शवों की पहचान जेब में रखी बैंक पासबुक से हुई। बताया गया है कि दोनों दोस्त थे। मथुरा में प्राइवेट काम करते थे। शनिवार तड़के अपाचे बाइक से नोएडा से आगरा जा रहे थे। जेब में रखी बैंक पासबुक से पहचान कानपुर के गांव बलुआपुर पोस्ट नाबस्ता निवासी रघुनाथ (30) और शिवली निवासी जसवंत (30) के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची थानाध्यक्ष रंजना सचान ने शवों को पीएम को भेज दिया है। परिजनों को सूचना दी है। पुलिस ने बताया कि अन्य जानकारी परिजनों के आने पर होगी। सीओ संजीव राय और थानाध्यक्ष रंजना सचान ने बताया अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। दोनों युवकों की मौत हो गई है। पुलिसकर्मियों ने देखा कि अपाचे बाइक (रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 78 एचएम 5591) सड़क पर क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके पास ही दो युवको के शव पड़े थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक का शव पूरी तरह कुचल गया था। थाना प्रभारी बल्देव ने बताया कि दोनों शवों को एंबुलेंस की सहायता से जिला मोर्चरी मथुरा भेजा गया है। मृतकों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है।

एसएसपी ने रिश्वत के आरोप में एसआई, सिपाही को किया निलंबित

● मांट थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर ने डायल 112 के सिपाही के जरिये लिए थे पैसे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मथुरा। पुलिस महकमे की छवि पर बट्टा लगाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएसपी का एक्शन जारी है। एसएसपी श्लोक कुमार ने एक एसआई और एक आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह कार्यवाही विवेचना के दौरान आरोपी से धाराओं में फेरबदल करने के नाम रिश्वत लेने के आरोपों के बाद की गई है। एसएसपी ने मामले की जांच कराई है। एसआई कपिल कुमार थाना मांट पर तैनात थे। आरक्षी सचिन शर्मा की ड्यूटी यूपी 112 थी। थाना मांट वर वर्ष 2024 में धारा 498, 323, 504, 506 आईपीसी व 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अंकित व अन्य पर दर्ज हुआ था। थाना मांट पर तैनात एसआई कपिल कुमार को इसकी विवेचना करनी थी। विवेचना के दौरान विवेचक ने धारा 307 आईपीसी की वृद्धि किये जाने की बात की और आरोपी के भतीजे को लैपटॉप पर दिखाया कि मामले में धारा 307 बढ़ाई गई है। इसके बाद उस समय मांट थाने पर तैनात आरक्षी सचिन शर्मा के माध्यम से धारा को हटाने की एवज में आरोपी पक्ष से पैसे एसआई कपिल कुमार ने तय कराये। पैसे एसआई को दिये गये लेकिन किन्हीं कारणों से एसआई से पैसे वापस हो गये। एसआई कपिल कुमार द्वारा अनुचित लाभ प्रलोभन से आरक्षी के माध्यम से रिश्वत लेने एवं अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, असंवेदनशीलता, स्वेच्छाचारिता, उदासीनता बरतने आदि के आरोप संज्ञान में आने पर

एसएसएसपी श्लोक कुमार ने एसआई कपिल कुमार व आरक्षी सचिन शर्मा के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलम्बन की कार्यवाही की है। एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया है कि पूर्ण मनोयोग से जनहित में कार्य करें, अनुशासन में रहकर ड्यूटी करें। अनुशासनहीनता बरतने पर सीधे निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

दोना, पत्तल की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान

● मथुरा के किशनपुर गांव में दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग, लाखों का सामान जलकर खाक।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मथुरा। थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम किशनपुर में शनिवार तड़के एक दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब चार बजे उठे धुएं को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों ने शोर मचाते हुए आसपास के लोगों को जगाया और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री के अंदर रखा लगभग सारा माल जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री स्वामी ने बताया कि उसने मेहनत-मजदूरी कर इस दोना पत्तल यूनिट को स्वरोजगार के रूप में स्थापित किया था, जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। आग लगने के चलते न केवल मशीनें बल्कि तैयार माल भी पूरी तरह जल गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग नौ लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

अचानक हुए इस हादसे से पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है। फैक्ट्री स्वामी ने बताया कि वह पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि यही उसके जीवनयापन का एकमात्र साधन थं उसने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है, ताकि वह दोबारा अपना रोजगार शुरू कर सके। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो नुकसान कुछ कम हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर मदद का भरोसा दिलाया है।

जिला प्रशासन ने अहोई अष्टमी की तैयारी शुरू की

● एसएसपी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गोष्ठी की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मथुरा। जिला प्रशासन ने अहोई अष्टमी के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अहोई अष्टमी पर गोवर्धन के राधाकुंड में भारी संख्या में स्नान को श्रद्धालु जुटते हैं। स्नान का पर्व रात के समय मनाया जाता है इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कुंड और आसपास सुरक्षा की दृष्टि से तैयारी की है। मान्यता है है कि निसंतान दंपति अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की अभिलाषा लिए हजारों की संख्या में दंपति अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। एसएसपी श्लोक कुमार, मनीष मीणा मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना व एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत द्वारा तहसील गोवर्धन सभागार में आगामी अहोई अष्टमी के दृष्टिगत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं सर्व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। वहीं एसएसपी मथुरा व मुख्य विकास अधिकारी

मथुरा द्वारा तहसील गोवर्धन मथुरा में सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर आम जनमानस की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों के नियमानुसार त्वरित निस्तारण हेतु तत्संबंधित को निर्देशित किया गया।

प्राथमिक विद्यालय बलरामपुर में मनाया गया वन्य जीव सप्ताह

● वन्य जीव हमारी धरोहर, संरक्षण सबका दायित्वः क्षेत्रीय वन अधिकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मथुरा। विकासखंड बलदेव के प्राथमिक विद्यालय बलरामपुर में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत छात्रों को वन्य जीवों की महत्ता और उनके संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय वन अधिकारी रवि कुमार ने छात्रों एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वन्य जीव केवल जंगलों की शोभा नहीं, बल्कि हमारी अनमोल प्राकृतिक धरोहर हैं। जिनकी रक्षा करना समाज के हर वर्ग का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इनकी रक्षा करना केवल वन विभाग का नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का साझा दायित्व है। वन दरोगा पुनीत शुक्ला ने सभी छात्रों तथा ग्रामवासियों को वन्य जीव संरक्षण की शपथ दिलाई और बताया कि भारत में जीव-जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक पूरे देश में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने वन पुलिस की भूमिका, दायित्व और वनों के लाभों से छात्रों को अवगत कराया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ जगदीश ने कहा कि वन्यजीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग हैं, क्योंकि हमारे देवी देवताओं ने भी इनके साथ सह अस्तित्व का संदेश दिया है। यही कारण है कि आदिकाल से वन्यजीवों का संरक्षण भारत की जीवन पद्धति का स्वाभाविक हिस्सा रहा है। कार्यक्रम के अंत में प्रश्न मंच का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता छात्रों को उपहार देकर वनों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर वन विभाग से जगपाल सिंह, राहुल कुमार, भारत सिंह और विद्यालय

वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत छात्रों को वन्य जीवों की महत्ता और उनके संरक्षण का संदेश दिया गया।

परिवार से डॉ जगदीश पाठक, डॉ ममता रानी, गीता सक्सेना, बिन्दु शर्मा, प्रेमचंद, पूजा, आकाश आदि की उपस्थिति मुख्य रही। संचालन डॉ जगदीश पाठक ने किया।

देश दुनिया ने देखा संघ का शक्ति प्रदर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष विजयादशमी उत्सव पर पथ संचलन से प्रारंभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिनेश भारद्वाज

नई दिल्ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपने शताब्दी वर्ष की ऐतिहासिक शुरुआत विजयादशमी उत्सव के अवसर पर दिल्ली के विभिन्न जिले में भव्य पथ संचलन से की। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 12 मंडलों के अंतर्गत 13 स्थानों पर मुख्य मार्गो से अनुशासित पथ संचलन निकाला गया। पूरे आयोजन में उत्साह, अनुशासन और संगठन की अद्वितीय छवि देखने को मिली।पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों की पंक्तियों ने अनुशासन और संगठन का परिचय देते हुए क्षेत्र का वातावरण राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कर दिया। नारी शक्ति, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी उल्लेखनीय रही। दिल्ली के प्रत्येक मंडल कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, वहीं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अतिथि के रूप में मार्गदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि विजयादशमी उत्सव केवल एक परंपरा नहीं बल्कि संगठन, सेवा और राष्ट्रसमर्पण का प्रेरणास्रोत है। जिले के माननीय संघ की पंच परिवर्तन योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए शताब्दी वर्ष को समाज जागरण का वर्ष घोषित किया। उन्होंने कहा कि यह समय केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का नहीं बल्कि भविष्य के संकल्पों को मजबूत करने का है।

वक्ताओं ने संघ की 100 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि 1940 से 1975 तक के कालखंड में विभाजन, युद्ध और आपातकाल जैसी परिस्थितियों में संघ ने कठिनाइयों का सामना किया। 1975 से 2000 के बीच संगठन का विस्तार हुआ और विभिन्न संगठनों की नींव रखी गई। 2000 के बाद समाज में व्यापक बदलाव और राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक निर्णय सामने आए। कोरोना काल में भी संघ ने सेवा कार्यों से समाज का साथ दिया। संघ के वरिष्ठ वक्ताओं ने कहा कि शताब्दी वर्ष केवल औपचारिक उत्सव का नहीं, बल्कि सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक समरसता जैसे क्षेत्रों में समाज तक पहुँच बढ़ाने का संकल्प वर्ष है। कार्यक्रम में यह भी उल्लेख किया गया कि संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने स्मृति सिक्का और डाक टिकट जारी कर विश्वास और सम्मान प्रकट किया है।

पथ संचलन के साथ आयोजित विजयादशमी उत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएँ और युवा उपस्थित रहे।जिला प्रचार प्रमुखअन्य सभी की पथ संचलन में पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने भाग लिया। समाज की सज्जन शक्ति ने फूलों की वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। वरिष्ठ संघ अधिकारियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। विजयादशमी का यह आयोजन न केवल दिल्ली के प्रत्येक जिले के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की दिशा और दशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव भी बना।

विकसित भारत बिल्डथान 12 वीं तक के छात्र लेंगे भाग

● इस बिल्डथान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में नवाचार, रचनात्मकता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मथुरा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में विकसित भारत बिल्डथान 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेशभर के कक्षा छह से 12 तक के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि छह अक्टूबर तय की गई है। इस बिल्डथान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में नवाचार, रचनात्मकता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना है। नवाचार से संबंधित यह प्रतियोगिता सभी सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में आयोजित की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और डायट प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिक से अधिक बच्चों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह देखना होगा कि छात्र-छात्राएं इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं या नहीं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम से संबंधित कांसेप्ट नोट, वीडियो और जिंगल्स पहले ही पत्र में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से साझा किए जा चुके हैं। इसके अलावा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाने के लिए विशेष वीडियो तैयार कराया गया है, जिसे सभी प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

चार विषयों में शामिल होंगे छात्र छात्राएं

जिला विद्यालय निरीक्षक रवीन्द्र सिंह ने बताया कि स्कूलों में विकसित भारत बिल्डथान-2025 का आयोजन किया जाएगा। नवाचार से संबंधित यह प्रतियोगिता सभी सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में आयोजित की जाएगी। बिल्डथान-2025 में कक्षा छह से 12वीं के विद्यार्थी भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य उन्हें इनोवेटिव सोच का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य परियोजना आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को सीखना है। इसमें प्रत्येक टीम चार राष्ट्रीय विषयों में से किसी एक में सम्मिलित होगी, जिनमें वोकल फार लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और समृद्ध भारत सम्मिलित हैं। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए विद्यालय छह अक्टूबर तक अपना निबंधन प्रतियोगिता करा सकेंगे। 12 अक्टूबर तक विद्यालय स्तर पर गतिविधियां होंगी, जिनमें मार्गदर्शन भी सम्मिलित हैं। 13 अक्टूबर को पूरे देश में लाइव बिल्डथान का आयोजन होगा।

निर्धारित पोर्टल पर होगी आइडिया की एंट्री

14 से 31 अक्टूबर तक आइडिया की एंट्री निर्धारित पोर्टल पर होगी तथा नवंबर माह में उनका मूल्यांकन होगा। दिसंबर में विजेता की घोषणा की जाएगी तथा कारपोरेट स्वीकृति दी जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को मेंटर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रतिभागी वीडियो या प्रोफोटाइप के रूप में अपने आइडिया को अपलोड करेंगे।

वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में 'मन महोत्सव' के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2025 समारोह की शुरुआत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली: वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग ने आज 'मन महोत्सव' के तहत परिसर में एक जीवंत जागरूकता मार्च के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2025 समारोह का उद्घाटन किया। इस मार्च में निदेशक डॉ. संदीप बंसल, प्राचार्य डॉ. गीतिका खन्ना, सभी अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक और मनोचिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज वर्मा के साथ-साथ संकाय, रेजिडेंट, छात्र और कर्मचारी शामिल हुए और इसका नेतृत्व किया। इस मार्च का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, कलंक को तोड़ना और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना था। इस वर्ष का विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह "सेवाओं तक पहुँच - आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य" विषय पर केंद्रित है। इसके अनुरूप, मान महोत्सव में पूरे सप्ताह आकर्षक और शैक्षिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी, जिनमें शामिल हैं- मनोचिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य पर पीजी क्विज़ प्रतियोगिता, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिताएं, मानसिक कल्याण पर युवाओं की आवाज़ के लिए माइक ड्रॉप इवेंट, विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा, संकट और आपात स्थिति के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पहुंच सुनिश्चित करने में चुनौतियों और समाधानों पर प्रकाश डालना। इस अवसर पर बोलते हुए, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल के निदेशक डॉ. संदीप बंसल ने समाज में सबसे वंचित और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मानसिक

स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने में सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। वीएमएमसी की प्रिंसिपल डॉ. गीतिका खन्ना ने जागरूकता के संदेश को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला, जबकि मनोचिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज वर्मा ने सप्ताह भर चलने वाले समारोह को सभी के लिए एक सहायक और समावेशी वातावरण बनाने के अवसर के रूप में रेखांकित किया।

नगर में निकली श्रीकृष्ण बलराम शिक्षा शोभायात्रा

● नगरवासियों ने किया पग पग पर स्वागत व आरती

आज मथुरा से उज्जैन के लिए करेगी प्रस्थान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मथुरा। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ के तत्वावधान में उज्जैन जाने वाली श्रीकृष्ण बलराम शिक्षा यात्रा के अंतर्गत शनिवार को नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का शुभारंभ भूतेश्वर स्थित श्रीबाबा आश्रम से हुआ, जो डीग गेट, मंडी रामदास, चौक बाजार, स्वामी घाट होते हुए विश्राम घाट पहुँची। यहाँ पर सामूहिक यमुना पूजन संपन्न हुआ। यात्रा में धर्मध्वजा, वृंदावन का बैंड, श्रीनाथजी एवं श्री यमुनाजी की झांकी, संकीर्तन मंडल, शहनाई वादन तथा श्रीकृष्ण बलराम के स्वरूपों की मनोहारी झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं।नगरवासियों ने स्थान स्थान पर पुष्पवर्षा और आरती कर यात्रियों का स्वागत किया। शोभायात्रा के मार्ग में श्री वामन भगवान महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक आरती एवं पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर समिति के संस्थापक श्याम शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष संजय हरियाणा, कार्यक्रम संयोजक संजय पिपरोनिया, महामंत्री अर्जुन पंडित, उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, कोषाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, मंत्री कुलदीप शास्त्री, हरिशंकर, दाऊदयाल पंडा सर्वेश चतुर्वेदी, तथा सोशल मीडिया प्रभारी दोमेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं उसी क्रम में नारायण दास ट्रस्ट के श्री गोपाल मंदिर की कार्यकारिणी द्वारा भी शोभायात्रा का स्वागत किया गया। ट्रस्टी मनीष अग्रवाल एडवोकेट ने कहा कि धर्म और शिक्षा का

श्रीकृष्ण बलराम शिक्षा यात्रा में शामिल लोग।

संगम ही समाज को सशक्त बनाता है। श्रीकृष्ण बलराम शिक्षा यात्रा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति, आस्था और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया जा रहा है। यह यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह समाज में आध्यात्मिक चेतना और एकजुटता का प्रतीक है। हम सबको ऐसे आयोजनों से प्रेरणा लेनी चाहिए और धर्मकार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस अवसर पर ट्रस्टी मनीष अग्रवाल एडवोकेट, प्रबंधक दीपक सिंघल, कार्यकारी अध्यक्ष संजय हरियाणा, प्रवक्ता श्याम शर्मा एवं अमित अग्रवाल एडवोकेट ने दीपिका अग्रवाल सीमा मोरवाल ने पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया।

थाना आईपी एस्टेट ने अवैध पटाखा आपूर्ति का भंडाफोड़ किया

नई दिल्ली: आगामी त्यौहारी सीज़न को देखते हुए, पटाखों पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर नज़र रखने और ऐसे विस्फोटकों के आपूर्तिकर्ताओं और भंडारण स्थलों की पहचान करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। 3 अक्टूबर को पुलिस थाना आईपी एस्टेट में अवैध पटाखों की बिक्री की सूचना प्राप्त हुई। गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, राउज़ एवेन्यू कोर्ट, डीडीयू मार्ग, दिल्ली के पास छापा मारा गया, जिसके दौरान एक व्यक्ति को पटाखों की भारी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर की गई आगे की तलाशी में मीना बाज़ार, जामा मस्जिद से अतिरिक्त पटाखे बरामद हुए।

यह अभियान सुश्री सुलेखा जगरवार, सहायक पुलिस आयुक्त/उप-मंडल कमला मार्केट के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में, घनश्याम किशोर, थाना प्रभारी/आईपी एस्टेट के निर्देशों पर और उप-निरीक्षक मुकेश तोमर की निगरानी में चलाया गया। टीम में उप-निरीक्षक मनीष, सहायक उप-निरीक्षक राजकुमार गिरी, हवलदार नदीम और कांस्टेबल राहुल शामिल थे।थाना आईपी एस्टेट टीम की त्वरित और सतर्क कार्रवाई से अवैध पटाखा विक्रेता को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया गया।गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद तौहीद आलम जिसकी आयु 44 वर्ष जो मीना बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली का निवासी है। उसके पास से 70.4 किलोग्राम अवैध पटाखे/ विस्फोटक

बरामद हुए। लगातार पूछताछ के दौरान, अभियुक्त ने खुलासा किया कि उसने त्योहारों के मौसम में लाभ कमाने के लिए अवैध रूप से बेचने के इरादे से हरियाणा से प्रतिबंधित पटाखे खरीदे थे। उसके आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यह तमाम जानकारियां निधिन वलसन, आईपीएस, पुलिस उप आयुक्त मध्य जिला, नई दिल्ली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।

भाजपा जिलाध्यक्ष के घर पर गोली चलाने वाले को लगी गोली

● मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही इतिहास

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मथुरा। भाजपा जिला अध्यक्ष के घर फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई एसओजी टीम और थाना छाता पुलिस की संयुक्त टीम ने की। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार बदमाश की पहचान विष्णु पुत्र प्रकाश निवासी सुनरख, थाना जैत के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक विष्णु कुख्यात लोकेश गैंग से जुड़ा हुआ है और भाजपा जिला अध्यक्ष के घर हुई फायरिंग की वारदात में वांछित था। शुक्रवार देर रात पुलिस टीम ने जब उसे घेरने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मौके से विष्णु को गिरफ्तार कर लिया और उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगाला रहा है और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। मथुरा में भाजपा जिला अध्यक्ष के

घर फायरिंग करने वाला बदमाश विष्णु पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। जैत थाना क्षेत्र के सुनरख निवासी विष्णु लोकेश गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है शुक्रवार देर रात एसओजी और छाता पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई। पुलिस उसके आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है।